Result Mitra Daily Magazine

RBI का हालिया रोजगार सम्बन्धी रिपोर्ट एवं भारत सरकार की प्रमुख रोजगार योजना

हालिया सन्दर्भ

- हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वित्त वर्ष 2023-24 के लिए रोजगार संबंधी एक आंकड़ा जारी किया है।
- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा जारी इस रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2023-24 में देश में रोजगार लगभग 6% बढ़ाने की बात कही गई है जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के रोजगार वृद्धि लगभग 3.2% थी।
- उल्लेखनीय है कि रिजर्व बैंक द्वारा देश के रोजगार संबंधी रिपोर्ट 'सिटी ग्रुप इंडिया' द्वारा जारी रोजगार संबंधी शोध रिपोर्ट के कुछ दिन बाद आया है जिसमें कहा गया था कि भारत अपनी 7 प्रतिशत के विकास दर के बावजूद रोजगार के समुचित अवसर पैदा करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

क्या कहता है RBI की रिपोर्ट (रिपोर्ट का आधार)

- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा उद्योग स्तर पर भारत की रोजगार की उत्पादकता को जानने के लिए KLEMS डेटाबेस के माध्यम से संपूर्ण भारतीय अर्थव्यवस्था सहित 27 उद्योगों को शामिल किया है।
- भारतीय रिजर्व बैंक के KLEMS डेटाबेस का तात्पर्य K से पूंजी, L से श्रम, E से ऊर्जा, M से सामग्री एवं S से सेवाएं हैं।
- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया ने इस KLEMS डेटाबेस में व्यापक क्षेत्रीय स्तरों (कृषि, विनिर्माण और सेवाएं) सहित अखिल भारतीय स्तरों के आकलन के आधार पर यह आंकड़ा जारी किया है।

आंकड़े

- रिजर्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा 9 जुलाई को जारी रोजगार संबंधी आंकड़े में कहा गया है कि वित्त वर्ष 2022-23 की तुलना में वित्त वर्ष 2023-24 में देश में रोजगार के अवसर में दोगुनी वृद्धि हुई है।
- 2023-24 के पूर्ण वित्त वर्ष में लगभग 4.67 करोड़ नौकरियों में वृद्धि के साथ भारत में कुल कार्यबल बढ़कर 64.33 करोड़ हो गया है।
- वित्त वर्ष 2022-23 में देश के कुल कार्यबल 59.67 करोड़ थी।
- इस आंकड़े में बताया गया कि वित्त वर्ष 2020-21 में देश में लगभग 7.8 करोड़ नौकरियों में वृद्धि हुई थी।

देश में रोजगार के अवसर पर क्या कहता है सिटी ग्रुप रिपोर्ट

- रोजगार संबंधी शोध रिपोर्ट में कहा गया है कि भारतीय जनसांख्यिकी वृद्धि को देखते हुए भारत अपने 7 प्रतिशत जीडीपी (GDP) वृद्धि के साथ भी अगले दशक तक पर्याप्त रोजगार के अवसर सृजन करने में सक्षम होता नहीं दिख रहा है।
- दिग्गज बैंकिंग कंपनी सिटी ग्रुप ने अपने रिपोर्ट में कहा कि हालांकि भारत में आधिकारिक बेरोजगारी दर सिर्फ 3.2% है लेकिन वर्तमान समय में नौकरियों के गुणवत्ता, संभावित अल्परोजगार एवं रोजगार के अवसरों का सृजन एक गंभीर मुद्दा है।
- सिटी ग्रुप के रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कुल रोजगार का लगभग 46% हिस्सा कृषि से संबंधित है जबकि कृषि क्षेत्र का भारत के जीडीपी में योगदान लगभग 20% से भी काम है।
- इस रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय जीडीपी में अधिक योगदान देने वाले विनिर्माण और सेवा क्षेत्र में रोजगार तुलनात्मक रूप से कम है।
- इस रिपोर्ट के अनुसार देश के कुल कार्यबल का सिर्फ 21% लोगों के पास 'वेतनभोगी' नौकरी है जो पूर्व कोविड काल के 24% से भी काम है।
- रिपोर्ट में कहा गया कि वर्ष 2018 से 2023 के बीच ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की हिस्सेदारी लगभग 67% रही जो धीमी ग्रामीण से शहरी प्रवासन की प्रक्रिया को दर्शाता है।
- सिटी ग्रुप के इस रिपोर्ट में कहा गया कि वर्तमान हालात में देश में केंद्र सरकार को लगभग 10 लाख सरकारी नौकरियों को भरे जाने की जरूरत है तथा अगले दशक तक प्रत्येक वर्ष 1.2 करोड़ रोजगार के अवसर सृजित किए जाने की जरूरत है।

नवीनतम पीएलएफएस (PLFS) रिपोर्ट

- सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय (MOSPI) ने मई 2024 में त्रैमासिक (जनवरी-मार्च) आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण (PLFS, Periodic Labour force survey) बुलेटिन जारी की।

सर्वे के प्रमुख बिंदु

- PLFS के इस सर्वे में कहा गया कि मार्च 2023 से मार्च 2024 के बीच 15 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियों के लिए शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर 6.8% से घटकर 6.7% हो गई।

Result Mitra

- महिला बेरोजगारी दर 2023 के 9.2% से घटकर वर्ष 2024 में 8.5% हो गई। शहरी क्षेत्र में महिला श्रम भागीदारी में वृद्धि (22.7% से बढ़कर 25.6%)
- शहरी क्षेत्रों में श्रम बल भागीदारी 2023 के 48.5% से बढ़कर 50.2%
- आवधिक श्रम बाल सर्वेक्षण (PLFS) को वर्ष 2017 में राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (NSSO) द्वारा शुरू किया गया था जो प्रत्येक तीन महीने के लिए श्रम बल भागीदारी दर (LFPR), श्रमिक जनसंख्या अनुपात (WPR), बेरोजगारी दर (UR) आदि का विवरण प्रस्तुत करती है।
- 15 मई 2024 तक PLFS की यह अब तक की 22 वीं बुलेटिन है।

भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे प्रमुख रोजगार सृजन योजनाएं

'आत्मनिर्भर भारत' रोजगार योजना

- आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना की शुरुआत 12 मई 2020 को कोविड-19 महामारी के दौरान रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए शुरू किया गया था।
- इस योजना के तहत कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) के साथ पंजीकृत करके एक हजार तक के रोजगार देने वाले कंपनी को शामिल किया जाना है जिसमें कर्मचारियों और नियोक्ता दोनों के अंशदान जो लगभग 24% के बराबर है।
- यह योजना मुख्य रूप से 1000 या उससे अधिक कर्मचारी वाले कंपनियों के कर्मचारियों के EPFO भुगतान को कवर करती है।
- जुलाई 2023 तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 8 लाख कर्मचारियों को EPFO के अंतर्गत पंजीकृत करके रोजगार के अवसर का सृजन किया जा चुका है।

प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना

- 1 अप्रैल 2016 को शुरू की गई प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, रोजगार सृजन के लिए संगठित क्षेत्र के कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) साथ पंजीकृत करने के लिए प्रोत्साहित करती है।
- इस योजना के तहत भारत सरकार नए यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (UAN) वाले कर्मचारियों को कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत लाकर कर्मचारी भविष्य निधि (EPF) में नियोक्ताओं के पूर्ण योगदान का भुगतान करती है।

राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना

- राष्ट्रीय कैरियर सेवा परियोजना को 20 जुलाई 2015 को भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा लांच किया गया।
- इस पंचवर्षीय मिशन मोड परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारत के नव युवाओं को रोजगार एवं कैरियर सम्बन्धी जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ निशुल्क ऑनलाइन कैरियर प्रशिक्षण देना है।

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार अभियान

Result Mitra

- 20 जून 2020 को शुरू की गई इस योजना का मुख्य उद्देश्य तत्काल रोजगार उपलब्ध कराना है।

पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना

- पंडित दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना की शुरुआत सितंबर 2014 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत 15 से 35 साल के ग्रामीण युवाओं के लिए प्लेसमेंट से जुड़ा एक कौशल विकास योजना है।

पीएम (PM) स्वनिधि योजना

- पीएम स्वनिधि योजना जिसे प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर योजना भी कहा जाता है, जून 2020 में लॉन्च किया गया था।
- इस योजना के अंतर्गत स्ट्रीट वेंडर्स को बिना किसी जमानत के स्वरोजगार के लिए ऋण प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम

- वर्ष 2008 में ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के तहत रोजगार सृजन के लिए प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी।
- 2020-21 में इस कार्यक्रम को 13544 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी गई है।
- इस योजना के अंतर्गत पारंपरिक कारीगरों में एवं बेरोजगार युवाओं को ऋण सहायता प्रदान करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्योग की स्थापना से स्वरोजगार के अवसर सृजित करना है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- 8 अप्रैल 2015 को शुरू की गई इस योजना का उद्देश्य गैर कृषि, गैर कॉपरेट लघु-सूक्ष्म उद्योगों के 10 लाख तक का ऋण प्रदान करना है।

उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना

- उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना की शुरुआत वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा मार्च 2020 में राष्ट्रीय विनिर्माण को बढ़ावा देने एवं 60 लाख नई नौकरियों को पैदा करने के उद्देश्य से 14 प्रमुख उत्पादन से जुड़ी क्षेत्रों के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि जारी की गई।

Result Mitra